तिब्बत देश

तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बांधने की चीनी साजिश

आखिरकार चीन की सरकार ने स्वीकार लिया है कि वह पनबिजली –उत्पादन के लिए तिब्बत की यार्लुंग त्सांग्पो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बना रही है।

इस बांध के अलावा भी तीस अन्य बांध इसी क्षेत्र में बनाये जा रहे हैं। भारतीय मीडिया और अन्य देशों में भी इस खतरनाक बांध के बारे में रिपोर्टें छपती रही हैं। लेकिन भारत सरकार का स्पष्टीकरण होता था कि उसे चीन द्वारा ऐसे किसी बांध को बनाये जाने की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसे चीन की सरकार ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। अब तो चीन सरकार का स्पष्टीकरण पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। लंबे समय तक पूरे विश्व को गुमराह करते रहने के बावजूद चीन की सरकार को सच स्वीकारना ही पड़ा।

यार्लुंग त्सांग्पो नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध केवल तिब्बत के लिए खतरा नहीं है। इससे भारत और बंगलादेश भी संकटग्रस्त हो जायेंगे। यार्लुंग त्सांग्पो दक्षिण–पश्चिम तिब्बत में लगभग चार हजार मीटर ऊँचे आंगसी ग्लेशियर से निकलकर पूरब की ओर सोलह सौ किलोमीटर तिब्बत में बहती है। इसके बाद यू टर्न लेती हुई यह भारतीय प्रदेश अरूणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जहाँ इसे सियांग नाम मिल जाता है। फिर असम में आती है। दिबांग ओर लोहित नदियों से संगम के बाद यही सियांग से ब्रह्मपुत्र हो जाती है।

यार्लुंग त्सांग्पो या त्सांग्पो से सियांग और अंततः ब्रह्मपुत्र कही जाने वाली तिब्बत से निकली यह नदी असम से बंगलादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलने के पूर्व गंगा नदी से संगम करती है। ब्रह्मपुत्र–गंगा के संगम स्थल पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित है। इस तरह स्पष्ट है कि तिब्बत में त्सांग्पो पर बन रहा विश्व का सबसे बड़ा बांध विश्व के सबसे बड़े डेल्टा को भी तबाह कर देगा। इस प्रकार चीन सरकार की यह कुटिल योजना अंतर्राष्ट्रीय चिंता एवं चिंतन का विषय है।

चीन सरकार का मत है कि वह त्सांग्पो नदी पर बिजली उत्पादन के लिए सामान्य बांध बना रही है। वह इस नदी के जल को न तो जमा करेगी और न ही इसके प्रवाह एवं जल की मात्रा को नियंत्रित करेगी। उसका कहना है कि वह त्सांग्पो या तिब्बत स्थित किसी अन्य नदी की दिशा को भी नहीं मोड़ेगी। लेकिन वास्तविकता अलग है। चीन की कथनी–करनी में अंतर है।

तिब्बत पर अपने अवैध आधिपत्य के समय से ही चीन की सरकार तिब्बत की प्राकृतिक संपदा एवं वहाँ के पर्यावरण को बर्बाद करती आ रही है। उसकी योजना दक्षिणी तिब्बत की नदियों के मार्ग को बदलकर उनके प्रवाह को उत्तरी क्षेत्र में पहुँचाने की है। चीन की निरंकुश साम्यवादी पार्टी एवं उसकी उपनिवेशवादी साम्यवादी सरकार को तिब्बत के लोगों के हित या विश्व जनमत, यहाँ तक कि चीन के आमलोगों के कल्याण की भी चिंता नहीं है। अन्यथा जबर्दस्त भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र में वह विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने का विनाशकारी कार्य नहीं करती।

चीन की आम जनता को भी इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि वह चीन सरकार के जन विरोधी कदमों का विरोध करे। तिब्बत में जरूर तिब्बती विरोध कर रहे हैं। परिणामतः उन्हें चीनी सरकार की दमनात्मक–हिंसात्मक कार्रवाइयों का शिकार होना पड़ रहा है। हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि चीन सरकार की क्रूरतापूर्ण कार्रवाई से बचने के लिए तथा चीनी सरकार की नृशंसता की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए तिब्बतियों को अपने ही देश में आत्मदाह एवं आत्महत्या के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। भगवान–बुद्ध के अनुयायी, अहिंसा–करूणा–मैत्री के उपासक तथा शांति एवं प्रकृति–संरक्षण के संदेशवाहक भिक्षु–भिक्षुणी स्वयं को समाप्त करने को विवश हैं।

अब भारत सरकार को चीन की सरकार से सीधी बात करनी है। कथित विनाशकारी बांध के सहारे चीन इच्छानुसार भारत में बाढ़ एवं अकाल उत्पन्न कर सकता है। तिब्बत में आंगसी ग्लेशियर को तबाह करने का नतीजा बंगलादेश को भी भुगतना होगा। भारत सरकार के लिए उचित है कि वह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर छोटे–छोटे बांध बनाए तथा बिजली–उत्पादन करे। तभी चीन के साथ सार्थक संवाद संभव है। जब त्सांग्पो (ब्रह्मपुत्र) नदी तिब्बत से बाहर भी बहती है, तो उस पर बांध बनाने का निर्णय चीन अकेले कैसे ले सकता है? उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना होगा।

भारत सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह भारतीय राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तथा सांस्कृतिक–आध्यात्मिक मूल्यों एवं बोद्ध दर्शन में निहित जीवन–दर्शन के संरक्षण के लिए तिब्बत में पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन की चीन सरकार द्वारा की जा रही बर्बादी का जमकर विरोध करे। विश्व स्तर पर वह तिब्बत समर्थकों का साथ दें और उनका भी समर्थन ब्रह्मपुत्र नदी के संरक्षण हेतु प्राप्त करे। यार्लुंग त्सांग्पो (सियांग या ब्रह्मपुत्र) पर तिब्बत में चीन सरकार द्वारा बनाये जा रहे संसार के सबसे बड़े बांध के निर्माण को रोकना ही एकमात्र रास्ता है। इसी रास्ते पर सभी तिब्बत समर्थकों तथा पर्यावरण–प्रेमियों के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने का समय आ गया है।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)

चीन में दो और भिक्षुओं ने खुद को आग लगाई

(सीएनएन, बोधगया, 9 जनवरी)

दक्षिण–पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में आत्मदाह कर लेने से एक पूर्व तिब्बती भिक्षु की मौत हो गई है, जबकि एक और भिक्षु गंभीर रूप से घायल हैं। इस तरह पिछले साल मार्च से अब तक चीन में आत्मदाह की यह 13वीं और 14वीं घटना हो गई है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ के अनुसार अबा (तिब्बती में क्वियांग) स्वायत्तशासी प्रशासनिक क्षेत्र के अबा काउंटी के एक चौराहे पर एक 22 साल के युवा ने खुद को आग लगा लिया, इसके तत्काल बाद वहां पुलिस ने पहुंच कर आग बुझाया और उसे स्थानीय अस्पताल ले गई। शिनहुआ के अनुसार 18 साल के एक दूसरे युवा की उसी दिन बाद में मौत हो गई जिसने एक होटल के पास खुद को आग के हवाले कर दिया था। हालांकि, अबा सरकार की प्रवक्ता ने सीएनएन से कहा कि उन्हें ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। तिब्बती आंदोलनकारी समूहों का कहना है कि आत्मदाह करने वाले लोगों ने चीनी शासन के विरोध में ऐसा किया है। तिब्बत की आज़ादी का समर्थन करने वाले लंदन स्थित संगठन फ्री तिब्बत के निदेशक स्टीफैनी ब्रिगडेन ने कहा, "आत्मदाह की इन नवीनतम घटनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि तिब्बत में फिलहाल हम जो कुछ भी देख रहे हैं वह चीनी आधिपत्य का लगातार और गहन अस्वीकार है। उन्होंने कहा, "यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए यह भारी लानत की बात है कि तिब्बत के विभिन्न हिस्सों में 14 लोग खुद को आग लगा चुके हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमें लगता है कि जब तक तिब्बत की गंभीर स्थिति के बारे में वैश्विक नेता आंखें मूंदे रहेंगे, विरोध में इस तरह का कृत्य जारी रहेगा। आत्मदाह की ज्यादातर घटनाएं अबा प्रशासनिक क्षेत्र और कीर्ति मठ में हुई हैं। कीर्ति मठ भी सिचुआन प्रांत में स्थित है जो कि संस्कृति के क्षरण से नाराज तिब्बतियों के आंदोलन का केंद्रबिंदु बन गया है। लेकिन चीन इन आरोपों का खंडन करता रहा है कि वह तिब्बत में दमन कर रहा है। चीन का दावा है कि तिब्बत में उसके शासन से तिब्बती लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। चीन का आरोप है कि निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा लोगों को इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रहे हैं,हालांकि दलाई लामा इसका खंडन करते रहे हैं। गौरतलब है कि दलाई लामा के कुछ प्रतिनिधियों ने साल 1951 में बीजिंग में एक समझौते पर हस्ताक्षर कर तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार की थी, लेकिन इस समझौते के तहत तिब्बत को स्वायत्तता देने की बात भी की गई थी। साल 1959 में चीनी शासन के खिलाफ तिब्बत में जनक्रांति विफल रही जिसके बाद दलाई लामा को निर्वासित होकर भारत आना पड़ा। दलाई लामा इस बात से इनकार करते रहे हैं कि वह तिब्बत की आज़ादी चाहते हैं, उनका कहना है कि वह तो वास्तविक स्वायत्तता चाहते हैं जिसके तहत तिब्बती प्रमुख मसलों पर खुद निर्णय ले सकें जैसे कि धर्म के पालन आदि पर। तिब्बत में साल 2008 की जनक्रांति, हिंसक अशांति और इसके बाद सैन्य कार्रवाई में कम से कम 18 लोग मारे गए और आंदोलनकारियों का कहना है कि तब से ही इस क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है।

"तिब्बत में सच्चाई है और इस सच्चाई की निश्चित रूप से जल्दी ही एक दिन विजय होगी। वास्तविकता को बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए खुश रहिए और मजबूत बने रहिए।"

दक्षिण–पश्चिमी चीन में तिब्बतियों ने दलाई लामा के चित्र के साथ प्रदर्शन किया

(बीजिंग, 17 जनवरी, एएनआई)

चीनी शासन के विरोध में कई तिब्बतियों द्वारा खुद को आग लगाने के कुछ दिनों के बाद दक्षिण–पश्चिमी चीन में भिक्षुओं समेत कई तिब्बतियों ने सरकारी अवज्ञा करते हुए दलाई लामा के चित्र लेकर प्रदर्शन किए हैं। हेराल्ड उन अखबार में छपे बयान के अनुसार सिचुआन प्रांत के सेदा काउंटी के जन सुरक्षा ब्यूरो के अधिकारी ने कहा कि सोमवार को करीब 100 तिब्बती एक जगह इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हाथ में दलाई लामा के चित्र ले रखे थे। पिछले माह शुरू हुए चीनी नव वर्ष की चर्चा करते हुए वांग ने कहा, "नए साल का समारोह नजदीक आ रहा है, इसलिए वे इस तरह की घटनाएं कर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।" वांग ने कहा कि पुलिस ने इस घटना को काबू किया है, हालांकि उन्होंने इसका और ब्योरा देने से इनकार किया। सेदा काउंटी की पुलिस ने भी कहा कि अधिकारियों ने भीड़ को काबू में कर लिया है, हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया कि सोमवार को हुई घटना में किसी तिब्बती को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। तिब्बतियों के विरोध प्रदर्शनों को लेकर चीन बहुत संवेदनशील है क्योंकि वे पश्चिमी क्षेत्र में उसके

नियंत्रण को चुनौती देते हैं और इससे चीन के अन्य हिस्सों में भी सरकार से गुस्साए लोगों का प्रदर्शन भड़कने का खतरा है।

पिछले एक साल में कम से कम 16 बौद्ध भिक्षु, भिक्षुणी और अन्य तिब्बतियों के खुद को आग लगा लेने की खबर है, अकेले इस महीने ऐसी चार घटनाएं हुई हैं। ऐसी ज्यादातर घटनाएं सिचुआन प्रांत के तिब्बती इलाकों में हुई हैं। ज्यादातर लोगों ने तिब्बत की आज़ादी और अपने आध्यात्मिक नेता परमपावन दलाई लामा की वापसी का नारा लगाते हुए ऐसा किया है। दलाई लामा 1959 में तिब्बत में चीनी शासन के खिलाफ हुई जनक्रांति के विफल हो जाने के बाद भारत चले गए थे। चीन एक दशक से भी ज्यादा समय से दलाई लामा को कलंकित करने की कोशिश कर रहा है, उन पर चीन आरोप लगाता है कि वे हिमालयी क्षेत्र को बाकी चीन से अलग करने का अभियान चला रहे हैं और तिब्बती इलाकों में स्थित धार्मिक संस्थाओं में चलाए जा रहे राजनीतिक शिक्षण कार्यक्रमों में भिक्षुओं को दलाई लामा की निंदा करने को कहा जाता है। दलाई लामा का कहना है कि तिब्बत को सिर्फ स्वायत्तता देने की मांग कर रहे हैं।

साइकिल रैली में भाामिल तिब्बती विद्यार्थी चेन्नई पहुंचे

(जी न्यूज डॉट कॉम, 31 जनवरी, चेन्नई)

चीन के भीतर तिब्बत को स्वायत्तता दिलाने के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए एक साइकिल रैली में शामिल तीन तिब्बती मंगलवार को चेन्नई पहुंचे। तीनों हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं। लुगोन थार, त्सेलो ग्याल और ग्यालत्सेन नाम के ये विद्यार्थी दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में यहां एक दिन के लिए रुके। इन तीनों ने गत 20 जनवरी को कर्नाटक के ब्यालकुप्पी से इस रैली की शुरुआत की थी जो कि एक प्रमुख तिब्बती बस्ती है। ये लोग 20 मार्च को दिल्ली पहुंचेंगे। इस बीच वे मुंडगोड, गोवा, पुणे, मुंबई, सूरत, गांधी नगर और जयपुर में रुकेंगे। इस बारे में ग्याल ने बताया, "इस समय हमारी सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। हम तिब्बत के बारे में लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं। भारत हमें नैतिक समर्थन देने वाला एक महान देश है। हम चीनी शासन के तहत स्वायत्तता चाहते हैं।

तिब्बत की समस्या एक न एक दिन जरूर सुलझेगीः परमपावन दलाई लामा

(बोधगया, 3 जनवरी, तिब्बत पोस्ट इंटरनेशनल)

दुनिया की मौजूदा कई समस्याएं निश्चित रूप से मानवीय देन हैं, लेकिन इनका समाधान भी मानव के पास ही है। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परमपावन दलाई लामा ने गत 3 जनवरी, मंगलवार को बोधगया में यह बात कही। परमपावन बोधगया में चल रहे 32वें कालचक्र शिक्षण के तीसरे दिन तिब्बत, चीन और हिमालयी क्षेत्र से आए लोगों को एक विशेष दर्शन के दौरान संबोधित कर रहे थे। इस विशेष दर्शन में तिब्बत, चीन और हिमालयी क्षेत्र से आए 8 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस दौरान परमपावन ने जोर दिया कि तिब्बत सहित दुनिया की कई समस्याएं मानवीय देन हैं। उन्होंने कहा कि तिब्बत की समस्या किसी प्राकृतिक विपदा से उपजी समस्या नहीं बल्कि तिब्बत के इतिहास एवं समृद्ध प्राकृतिक विरासत जैसी पहलुओं पर चीनी प्रशासन में समझ की कमी की वजह से है। उन्होंने कहा, "तिब्बत में सच्चाई है और इस सच्चाई की निश्चित रूप से जल्दी ही एक दिन विजय होगी। वास्तविकता को बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए खुश रहिए और मजबूत बने रहिए।"

परमपावन ने कहा कि निर्वासन में रह रहे तिब्बती आज़ादी के साथ रहते हुए, निष्पक्ष एवं सच्चे लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना रहे हैं, लेकिन उन्होंने तिब्बत में दमन का सामना कर रहे तिब्बतियों के प्रति अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "हर व्यक्ति खुशी चाहता है, कोई भी समस्या नहीं चाहता और अज्ञानता सभी समस्याओं की जड़ है।" तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा कि करीब छह दशक के चीनी कब्जे के तहत तिब्बत की जनता पीड़ित है, लेकिन उनके साहस और ताकत को कोई हिला भी नहीं सका है और वह मजबूत बने हुए हैं। उन्होंने कहा, "तिब्बत की असली मालिक तिब्बत के भीतर रहने वाली तिब्बती जनता है। आप सब उसका हिस्सा हो। पिछले करीब 60 साल से जब से मैंने तिब्बत की राजनीतिक जिम्मेदारी ली थी तीनों प्रांतों की तिब्बती जनता को चीनी नियंत्रण के दौरान भारी कष्ट भोगना पड़ रहा है।" परमपावन ने इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध धर्म को समझने की जरूरत है ताकि ऊंचे स्तर के धार्मिक विश्वास की बहाली हो सके। उन्होंने कहा, "मैं हमेशा

अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा, "हमें इन खबरों पर गहरी चिंता है कि पिछले कुछ दिनों में तीन और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लगातार इस मसले को चीन के सामने उठाया है।"

"ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तिब्बतियों का जीवन के प्रति वैसा दृष्टिकोण नहीं है जैसा कि शहरों में रहने वालों का है।"

यह कहता रहा हूं कि अध्ययन और उसे व्यवहार में लाना बहुत जरूरी है, लेकिन यह साथ–साथ होना चाहिए। धार्मिक विश्वास अकेले काफी नहीं है। धार्मिक विश्वास के पीछे कोई दलील होनी चाहिए। हम जो कुछ अध्ययन से सीखते हैं, उसे अपने दैनिक जीवन में गंभीरता से लागू करने की जरूरत है।"

उन्होंने कहा कि करीब 300 खंडों के गौतम बुद्ध के शिक्षण को सिर्फ प्रार्थना और साष्टांग प्रणाम का विषय नहीं बनाना चाहिए बल्कि हमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अध्ययन और विश्लेषण में शामिल होना होगा। " परमपावन ने कहा, "कई दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन में करीब 30 लाख लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है। चीन के 1.3 अरब लोगों को सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है और हमारे प्राचीन परंपरा एवं समझ से हर चीनी व्यक्ति में यह निर्णय करने की क्षमता है कि क्या सही है और क्या गलत।"

तिब्बती अधिकारियों के अनुसार 63 देशों के भक्त 10 दिवसीय कालचक्र शिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं जिनमें हिमालयी क्षेत्रों से 35,000 बौद्ध, एक हजार ताइवानी, एक हजार से ज्यादा भारतीय, एक हजार से ज्यादा चीनी, तिब्बत से आए करीब 8000 तिब्बती और 20 हजार से ज्यादा बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियां शामिल थे।

डर में जी रहे तिब्बती, चीन ने विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती बढ़ाई

(सेबेस्टियन ब्लांक, एएफपी, 28 जनवरी, चेंगदू)

शहर की करीब 1.4 करोड़ जनसंख्या में ज्यादातर हान चीनी नस्ल के लोग हैं।

चेंगदू के तिब्बती इलाके में एक छोटे से मकान में बैठे एक घबराए युवा भिक्षु बताते हैं कि किस तरह से पुलिस निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिससे चीन के तिब्बती इलाकों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। यह भिक्षु जिस लामा मंदिर में रहते हैं वह यहां से 15 घंटे मोटर यात्रा के बाद आता है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दक्षिण–पश्चिमी सिचुआन प्रांत के ऊंचे तिब्बती पठार पर स्थित इस मंदिर पर विरोध प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस तीन बार गोलीबारी कर चुकी है जिसमें कम से कम तीन लोग मारे गए हैं और दर्जनों अन्य घायल हुए हैं। जब गोलीबारी की घटनाएं हुईं तब 28 साल के यह युवा भिक्षु (सुरक्षा कारणों से उनका नाम हम नहीं छाप रहे) वहां नहीं थे, लेकिन उन्होंने बताया कि अपने दोस्तों से उन्हें इन हत्याओं की जानकारी मिली है। सिचुआन प्रांत की राजधानी चेंगदू में एक टीहाउस में बैठे दूध वाली तिब्बती चाय पीते और माला फेरते इन भिक्षु की घबराहट से पता चल जाता है कि इस प्रांत में माहौल कितना तनावपूर्ण है जहां लगातार आत्मदाह की कई घटनाओं के बाद वैसे ही सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, "उन्होंने कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने कुछ नहीं किया है। इससे लोगों में असंतोष और बढ़ रहा है।"

भारत में रहने वाले निर्वासित तिब्बतियों के अनुसार इस माह तिब्बत के पास स्थित सिचुआन प्रांत में कम से कम 136 तिब्बती नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है या पुलिस ने उन्हें गायब कर दिया है। भिक्षु ने कहा, "हम शांति प्रेमी हैं और हमें शांति की उम्मीद है।" उन्होंने बताया कि उनके मठ में अनिवार्य रूप से 'पुनर्शिक्षा' क्लास थोपे गए हैं जिनमें राजनीतिक एवं तथाकथित देशभक्तिपूर्ण पाठों की बहुलता होती है। चीन सरकार ने कहा है कि सेदा और लुहुओ कस्बों में हुए टकराव के दौरान दो तिब्बती मारे गए हैं, इनमें से एक पुलिस की गोली से मरा क्योंकि भीड़ के हिसंक हो जाने के बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि रंगतांग काउंटी में एक और तिब्बती प्रदर्शनकारी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन स्थानीय सरकारी अधिकारी इस बात से इनकार कर रहे हैं। असल में तिब्बती इलाकों में यह अशांति ऐसे माहौल में और बढ़ती जा रही है जब पिछले एक साल के भीतर 16 लोग चीनी शासन के खिलाफ आत्मदाह का प्रयास कर चुके हैं (इस महीने ही ऐसी चार घटनाएं हुई हैं)। युवा भिक्षु के मकान के बाहर दर्जनों वर्दी धारी और सादे कपड़ों में पुलिस के जवान सड़क पर तैनात हैं ताकि हम किसी स्थानीय नागरिक से बात न कर सकें। चीन सरकार ने प्रभावित इलाकों में विदेशी पत्रकारों के जाने पर रोक लगा दी है जिससे इलाके के हालात का स्वतंत्र तौर पर जायजा लेना लगभग असंभव हो गया है।

कुछ घंटों पहले ही पुलिस ने एएफपी के दो पत्रकारों को हिरासत में लिया है जो अबा प्रशासनिक क्षेत्र में स्थित उस कस्बे में घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां ज्यादातर चीन विरोधी प्रदर्शन हुए हैं। छह घंटे की मोटर यात्रा कर इन पत्रकारों को चेंगदू वापस छोड़ने के बाद पुलिस ने कहा, "भू स्खलन की वजह से उस इलाके में जाना संभव नहीं है।" इसके एक दिन पहले ही दो अन्य पत्रकारों को तिब्बती इलाकों की तरफ जाने वाले रास्ते पर रोक दिया था और उन्हें यह कहकर लौटने को मजबूर किया गया था, आगे

'बर्फबारी हो रही है।'

आर्थिक तरक्की के माहौल में चेंगदू एक विशाल आधुनिक शहर में तब्दील हो गया है और यहां तिब्बती समुदाय अल्पसंख्यक है। शहर की करीब 1.4 करोड़ जनसंख्या में ज्यादातर हान चीनी नस्ल के लोग हैं। हालांकि, दोनों समुदायों के रिश्तों में खुले तौर पर कोई खटास नहीं दिखता है। चेंगदू में रहने वाली सुओ लांग वा झांग ने बताया कि उनके कई हान चीनी लोग दोस्त हैं और उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि हो सकता है वह गैर तिब्बती से शादी करें। तिब्बत से आई युवा तिब्बती महिला ने कहा, "ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तिब्बतियों का जीवन के प्रति वैसा दृष्टिकोण नहीं है जैसा कि शहरों में रहने वालों का है।" झांग ने कहा कि वह कभी यह नहीं चाहेंगी कि चीन विरोधी दंगे फिर से शुरू हों जैसा कि साल 2008 में तिब्बत की राजधानी ल्हासा और अन्य इलाकों में हुए थे। उनकी दोस्त 20 साल की सांग दोंग जिन मेई एक बिजनेस स्कूल की छात्रा हैं और कई बुजुर्ग तिब्बतियों के विपरीत धाराप्रवाह मंदारिन (चीनी) भाषा बोलती हैं, वे चीनी समाज में अच्छी तरह से घुल–मिल गई लगती हैं। उन्होंने कहा, "मैं एक खुशहाल जीवन जीना चाहती हूं और अपना जीवन स्तर सुधारना चाहती हूं।" हालांकि, दोनों लड़कियों को यह उम्मीद है कि वे एक दिन ल्हासा लौटेंगी जो कि यहां से दो दिन की ट्रेन यात्रा के बाद आता है।

लेकिन चीन के तिब्बती इलाकों में 'सांस्कृतिक नरसंहार और नागरिक अधिकारों के दमन' की लगातार आलोचना करने वाले संगठन फ्री तिब्बत के अनुसार हाल के दिनों में ल्हासा में पुलिस बलों की संख्या काफी बढ़ा दी गई है। संगठन के निदेशक स्टीफेनी ब्रिगडेन ने कहा,"लोगों में डर बिठा देने और उन्हें आवाज़ उठाने से रोकने के लिए चीनी प्रशासन आम तिब्बतियों के खिलाफ भी धमकी और निगरानी का सहारा ले रहा है।" हालांकि,बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी अधिकारी हमेशा ऐसे आरोपों का खंडन करते रहे हैं। उनका इस बात पर जोर है कि तिब्बतियों को पूरी धार्मिक आज़ादी मिल रही है और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारी प्रयास किए जा रहे हैं। वे दलाई लामा पर अशांति को बढ़ावा देने और तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन 1959 में ही चीनी शासन के खिलाफ हुई जनक्रांति के विफल रहने के बाद भारत चले गए तिब्बती आध्यात्मिक गुरू इसका खंडन करते हैं।

तिब्बत में आत्मदाह की घटनाओं से अमेरिका चिंतित

(एएफपी, 9 जनवरी, 2012, वाशिंगटन)

अमेरिकी सरकार ने सोमवार को कहा कि उसे तिब्बती भिक्षुओं के आत्मदाह करने पर 'गंभीर चिंता' है और इन घटनाओं से यह साबित होता है कि चीन में धार्मिक आज़ादी पर अंकुश को लेकर भारी कुंठा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता विक्टोरिया न्यूलैंड ने कहा, "हमें इन खबरों पर गहरी चिंता है कि पिछले कुछ दिनों में तीन और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लगातार इस मसले को चीन के सामने उठाया है।" सरकारी मीडिया का कहना है कि उत्तर–पश्चिमी चीन के क्विंघई में खुद को आग लगा लेने वाले एक तिब्बती भिक्षु की मौत हो गई, इस तरह पिछले एक साल से भी कम समय में चीन के तिब्बती क्षेत्रों में खुलकर जताए जा रहे विरोध में 15 लोग खुद को आग लगा चुके हैं। पहली बार तिब्बती इलाकों में इस प्रकार की मौतें देखी जा रही है। ज्यादातर आत्मदाह की घटनाएं पड़ोसी सिचुआन प्रांत में हुई हैं जहां मानवाधिकार संगठनों के अनुसार धार्मिक दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आत्मदाह की लगातार घटनाओं का हवाला देते हुए न्यूलैंड ने कहा, "इस तरह की घटनाओं से साफतौर पर पता चलता है कि चीन के भीतर धार्मिक आज़ादी सहित मानवाधिकारों पर गहरे प्रतिबंध के खिलाफ भारी गुस्सा और कुंठा है। हमने कहा है कि चीन सरकार की नीतियां प्रतिकूल हैं।" उन्होंने कहा कि, "अमेरिका ने चीन सरकार से यह आग्रह भी किया है कि तिब्बत पर अपना नियंत्रण ढीला करने के लिए उसे एक सकारात्मक संवाद कायम करना चाहिए और पत्रकारों, राजनयिकों तथा अन्य प्रेक्षकों को वहां जाने की इजाजत देनी चाहिए ताकि वे वहां के हालात की सही जानकारी दे सकें। साथ ही, सभी नागरिकों के मानवाधिकार का सम्मान करना चाहिए।" अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर माह में भी इसी तरह का बयान जारी किया था। नवंबर माह में एशिया–प्रशांत सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए होनोलुलु का दौरा करने वाली अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी तिब्बत में आत्मदाह की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई थी।

भारत स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार ने कहा है कि वह आत्मदाह को प्रोत्साहित नहीं करती, लेकिन ऐसा करने के पीछे के हताशा को समझ सकती हैं। भारत

दोरजी ने बताया, "चीन ने हमारे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जासूस भेजे हैं, लेकिन हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीटीए के भीतर सब कुछ पारदर्शी है।

क्या भारत इस गुट का नेता बनने को तैयार है?

में रहने वाले हजारों तिब्बती ने बौद्ध बहुल इलाके (तिब्बत) में चीनी शासन की आलोचना के लिए विरोध प्रदर्शन और प्रार्थना में शामिल हुए। दलाई लामा सुरक्षा को देखते हुए साल 1959 में तिब्बत से भारत आ गए थे। उन्होंने जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की थी जिससे चीन काफी नाराज हुआ था।

अमेरिका द्वारा तिब्बती क्षेत्रों में आत्मदाह पर चिंता जताने से चीन नाराज

तिब्बती मठों और ननरियों में चलाए जा रहे चीन सरकार के तथाकथित 'देशभक्तिपूर्ण शिक्षा' अभियान का तिब्बतियों में व्यापक विरोध है और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी इसकी आलोचना कर रहे हैं।

(टाइम डॉट कॉम, 12 जनवरी, 2012)

चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने अमेरिकी समकक्ष को सलाह दी है कि वे तिब्बत के मामले में टांग अड़ाने से बाज आएं। इस हफ्ते अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने तिब्बती क्षेत्रों में लगातार जारी आत्मदाह के सिलसिले पर 'गंभीर चिंता' जताई थी जिसमें मार्च, 2011 से अब तक कम से कम 11 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी महीने चीन के दमनकारी शासन के विरोध और निर्वासित आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की वापसी की मांग करते हुए तीन तिब्बती खुद को आग लगा चुके हैं। इस तरह की सबसे नवीनतम घटना गत 8 जनवरी को हुई, जब चीन के तिब्बती बहुल प्रांत क्विंघई में 42 साल के एक 'जीवित बुद्ध' (भिक्षु) ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा ली। लेकिन बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिउ वेइमिन इस घटना पर चिंता जताने वाले अमेरिका पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, "हम इस तरह की टिप्पणियों और तिब्बत मसले का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने की परिपाटी का सख्ती से विरोध करते हैं। इससे चीन की सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता भंग हो सकती है।" गौरतलब है कि पिछले साल मार्च से अब तक पंद्रह तिब्बती भिक्षु, भिक्षुणी या पूर्व भिक्षु बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ हताशा भरे कदम उठाते हुए खुद को आग लगा चुके हैं क्योंकि इस तरह से वे तिब्बती लोगों के अधिकारों के बारे में पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे–जैसे इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं चीन तिब्बत के बारे में अपना जनसंपर्क अभियान तेज करता जा रहा है जिसमें बिना किसी सबूत या विवरण के यह आरोप लगाया जा रहा है कि दलाई लामा एवं उनके समर्थक इस तरह की आत्मदाह की घटनाओं की साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ दलाई लामा का कहना है कि तिब्बत के प्रति चीन की 'निर्दयी एवं अतार्किक' नीतियों जैसे धार्मिक एवं भाषाई प्रतिबंध आदि से तिब्बती इस तरह गुस्से वाले कदम उठाने को प्रेरित हो रहे हैं। गत 11 जनवरी को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े बीजिंग के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में चेतावनी दी है, "चीन का तिब्बती क्षेत्र धर्म के नाम पर उपद्रवी राजनीति से ग्रस्त है। इससे दलाई समूह और पश्चिमी देशों का हित सधता है।दलाई समूह के स्वार्थ और निर्दयता को पश्चिमी देशों द्वारा सावधानी से पेश किया जाता है और तथ्य तो यह है कि तिब्बत में आत्मदाह की घटनाएं जितनी ही बढ़ेंगी, दलाई लामा समूह के लिए जीवन उतना ही आसान होगा।" नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हस्ती पर इस तरह के अशिष्ट हमले का समर्थन करने वाले अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बहुत कम होंगे। इसके बावजूद चीन सरकार आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के खिलाफ अपना अभियान जारी रखे हुए है जिनके लिए तिब्बती कक्षाओं एवं कार्यस्थलों में दशकों से चल रहे दलाई लामा विरोधी दुष्प्रचार के बावजूद तिब्बतियों के मन में बहुत सम्मान है। इस माह तिब्बती कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख छेन कुआंगो नामक एक गैर तिब्बती को बनाया गया है। उनके नाम का मतलब होता है 'समूचा देश'। सरकारी अखबार चाइना डेली के अनुसार छेन ने तिब्बती मठों पर नियंत्रण और मजबूत करने का शपथ लिया है और भिक्षुओं से आग्रह किया है कि वे मौजूदा एकता एवं स्थिरता को बनाए रखें और दलाई लामा समूह की अलगाववादी गतिविधियों के खिलाफ प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई लडें। चीन अपने जनसंपर्क अभियान के तहत ही इस साल एक अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका 'तिब्बत स्टडीज' शुरू करने जा रहा है जिसमें तिब्बत के बारे में 'पश्चिमी नजरिए' का जवाब दिया जाएगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि चीन सरकार की इस पत्रिका में दलाई लामा के बारे में कभी सकारात्मक चीजें नहीं छपेंगी।

बोधगया में हजारों चीनी जासूसों के पहुंचने का संदेह

(फायूल डॉट कॉम, 2 जनवरी, बोधगया)

पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के सुरक्षा विभाग के मंत्री ने कहा कि बोधगया में चल रहे परमपावन दलाई लामा के कालचक्र शिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चीनी जासूसों के

घुस जाने का डर है। मंत्री गोडुप दोरजी ने पत्रकारों को बताया, "हमें जो सूचना मिली है उसके मुताबिक हमें संदेह है कि कालचक्र समारोह में 1000 से 1500 तक चीनी जासूस आए हैं। इन जासूसों को चीन ने तिब्बती नेताओं और निर्वासित समुदाय में उनकी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए भेजा है।" उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से शुरू होने वाले इस दस दिवसीय कालचक्र शिक्षण में शामिल होने के लिए तिब्बत से करीब 7 हजार तिब्बती भारत आए हैं। दोरजी ने बताया, "चीन ने हमारे बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जासूस भेजे हैं, लेकिन हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, सीटीए के भीतर सब कुछ पारदर्शी है। इसके पहले कई अवसरों पर परमपावन दलाई लामा खुले तौर पर संदिग्ध चीनी जासूसों से यह अनुरोध कर चुके हैं कि वे निर्वासित तिब्बतियों के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बिना कोई नमक–मिर्च लगाए सही–सही जानकारी पहुंचाएं।

तिब्बत से आई हाल की खबरों से भी संकेत मिलता है कि तिब्बत के मठों में चीनी जासूसों की संख्या साल 2008 में हुई जनक्रांति के बाद तेजी से बढ़ी है। निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्य एवं चीन विशेषज्ञ बावा कालसांग ग्यालत्सेन ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि तिब्बत के गांवों में करीब 20,000 चीनी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है ताकि 'चीन के लिए देशभक्ति और प्यार बढ़े' और 'तिब्बतियों के दिमाग को बदला जा सके'। तिब्बती सांसद ने कहा, "जब चीनी अधिकारी गांवों का दौरा करते हैं तो आमतौर पर ग्रामीण अपने वेदी या दीवारों पर चीनी नेताओं के चित्र लगा देते हैं, लेकिन उनके जाते ही ये चित्र उतार दिए जाते हैं। हालांकि, अब उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और उन्हें भारी दमन का सामना करना पड़ रहा है। तिब्बत के गांवों में घुसपैठ करने का यह कदम तिब्बत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नव नियुक्त बॉस छेन क्वांगुओ की नीतियों में से एक है।

तिब्बती मठों और ननरियों में चलाए जा रहे चीन सरकार के तथाकथित 'देशभक्तिपूर्ण शिक्षा' अभियान का तिब्बतियों में व्यापक विरोध है और अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच ने पिछले साल एक बयान जारी कर कहा कि तिब्बत में बढ़ी अशांति एवं तनाव के लिए चीनी प्रशासन की दमनकारी और उकसाऊ नीतियां जिम्मेदार हैं।

भारतीय सीमा तक पहुंचेगा चीन का रेल नेटवर्क

(द हिंदू डॉट कॉम, 18 जनवरी, बीजिंग)

चीन ने घोषणा की है कि वह तिब्बत तक विस्तृत अपने रेलवे मार्गों को बढ़ाकर भारतीय सीमा के नजदीक दो शहरों तक ले जाएगा और वह इसे नेपाल के भीतर तक ले जाने पर भी विचार कर रहा है। चीनी अधिकारियों ने इस हफ्ते यह जानकारी दी है। ल्हासा से अरुणाचल की सीमा के पास स्थित कस्बों शिगाजे (तिब्बती में शिगास्ते) और निंगची तक पहुंचने वाले ये रेल मार्ग तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र की पंचवर्षीय विकास योजना(2011–15) के तहत बनने वाली प्रमुख परियोजनाएं होंगी जिनकी घोषणा बुधवार को की गई है। इसके अलावा सरकारी समाचार एजेंसी शिनहुआ ने यह खबर भी दी है कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की काठमांडू यात्रा के दौरान तिब्बत से नेपाल तक रेलमार्ग बिछाने पर भी विचार हुआ है। शिनहुआ में छपे बयान में नेपाल के राष्ट्रपति राम बरन यादव ने कहा है, "नेपाल और तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र तक जाने वाले रेल मार्ग से दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे।"

टीएआर के विकास एवं सुधार आयोग के प्रमुख जिन शिजुन ने एक बयान में कहा कि यह रेलवे परियोजनाएं 'पर्यटन को बढ़ाने और प्राकृतिक संसाधनों की ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी'। चीनी अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य तिब्बत के सीमावर्ती इलाकों में विकास लाने के लिए संपर्क मार्गों का विकास करना है। हालांकि, भारतीय रक्षा अधिकारियों ने सीमा के नजदीक बनने वाले इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सामरिक निहितार्थों को लेकर चिंता जताई है। बयान में कहा गया है कि ल्हासा से शिगाजे तक क्विंघई–तिब्बत रेल मार्ग का विस्तार कार्य 2015 तक पूरा हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना के तहत क्विंघई–तिब्बत मार्ग का विस्तार करते हुए ल्हासा से निंगची तक एक रेलमार्ग भी बिछाया जाएगा। सितंबर, 2010 में ही शिगाजे रेलमार्ग पर कार्य शुरू हो चुका है और समूचे बजट की करीब एक–चौथाई 53.8 करोड़ डॉलर राशि पिछले साल के अंत तक खर्च की जा चुकी है। शिनहुआ के अनुसार 253 किलोमीटर का यह रेलमार्ग 90 किलोमीटर लंबी यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र)की विशाल घाटी से होकर गुजरेगी। इस रेलमार्ग से हर साल 83 लाख टन माल की ढुलाई हो सकेगी।

शंघाई के वाणिज्य दूतावास में नियुक्त भारतीय राजनयिक एस. बालाचंद्रन जब दो भारतीयों की रिहाई की कोशिश के लिए अदालत पहुंचे थे तो चीनी व्यापारियों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया जिससे उन्हें चोटें आईं।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1 तिब्बत से करीब 7000 तिब्बती नागरिक हिमालय पार कर बोधगया में 1 से 10 जनवरी, के लिए आए ।

2 चीन ने अरुणाचल प्रदेश का 'अपना हिस्सा' मांगा।

3 तिब्बत के निहत्थे तिब्बतियों पर चीनी पुलिस की गोलीबारी के खिलाफ प्रदर्शन

4 पूर्वी तिब्बत के ड्रांगो में सशस्त्र चीनी पुलिस अधिकारी।

5 एक पुरानी फोटो में लोबसांग जामयांग। नाबा के निवासी 22 साल के इस तिब्बती युवा ने मठ।

6 एक फाइल फोटो में राजदूत गैरी लॉक।

7 'तिब्बत के लिए साइक्लिंग' रैली तमिलनाडु के चेन्नई शहर पहुंची।

8 23 जनवरी, 2012 को शुरू होने वाले चीनी नए साल से पहले एक लाख से ज्यादा चीनी लगाना अनिवार्य है।

9 सिलिगुड़ी के बाहरी इलाके में 20 अक्टूबर, 2011 को टाशी गोमांग स्तूप पर तिब्बत के तिब्बत में लगातार कई बौद्ध भिक्षुओं के आत्मदाह के बाद चीनी प्रशासन ने जो सख्त में विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं।

10 पूर्वी तिब्बत के ड्रांगो में गत 23 जनवरी, 2012 को चीनी पुलिस की गोलीबारी से मारे

(9)

(8)

♦ आंखों देखी

(3)

(4)

कैमरे की आंख से

में 1 से 10 जनवरी, 2012 तक चलने वाले दलाई लामा के 32वें कालचक्र उपदेश में शामिल होने

खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नई दिल्ली में तिब्बती विद्यार्थियों ने एक कफन मार्च निकाला।

इस तिब्बती युवा ने गत 14 जनवरी को नाबा कस्बे की सड़क पर आत्मदाह कर लिया। फोटोः कीर्ति

लाख से ज्यादा चीनी कम्युनिस्ट नेताओं के चित्र तिब्बती मठों और आम घरों में बांटे गए हैं जिनका

स्तूप पर तिब्बत के समर्थन में हुई रैली में हाथ में मोमबत्ती लेकर शामिल होते तिब्बती भिक्षु।
ासन ने जो सख्त कार्रवाई की है उसके खिलाफ भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बतियों ने पूरे देश

ो गोलीबारी से मारे गए 49 साल के नोर्पा योनतेन।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(5)

(7)

(6)

भारतीय राजनयिक एस. बालाचंद्रन के साथ चीन में दुर्व्यवहार, भारत ने विरोध जताया

(ईटी ब्यूरो, 3 जनवरी, 2012)

चीन ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन एम पैन्गिंग को यह कहते हुए वीजा देने से इनकार कर दिया था कि अरुणाचल तो दक्षिणी तिब्बत का ही हिस्सा है और वहां के नागरिक को चीन में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है।

भारत ने सोमवार को यहां चीनी दूतावास के उप प्रमुख को बुलाकर उनसे चीन के शहर यिउ की एक अदालत में एक भारतीय राजनयिक के साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत की। शंघाई के वाणिज्य दूतावास में नियुक्त भारतीय राजनयिक एस. बालाचंद्रन जब दो भारतीयों की रिहाई की कोशिश के लिए अदालत पहुंचे थे तो चीनी व्यापारियों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया जिससे उन्हें चोटें आईं। स्थानीय व्यापारियों ने अपने कुछ बकाए की मांग करते हुए इन भारतीय व्यापारियों को बंधक बना लिया था। यह घटना 31 दिसंबर की रात की है जब बालाचंद्रन कोर्ट से बाहर निकल रहे थे और उनके साथ चिपककर दोनों बंधक भारतीय व्यापारी दीपक रहेजा और श्यामसुंदर अग्रवाल भी चल रहे थे। चीन के व्यापारियों की पिटाई से एस. बालाचंद्रन बेहोश हो गए। इसके तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

एक सरकारी सूत्र ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने उसी रात नई दिल्ली में नियुक्त चीनी दूतावास में उप प्रमुख को बुलाया था। यह नई दिल्ली में एक समारोह में दलाई लामा के भाषण को लेकर चीन एवं भारत के बीच कहा–सुनी के एक माह बाद ही हुआ है। इस कहा–सुनी के बाद नाराज चीन ने सीमा वार्ता को रद्द कर दिया था। बीजिंग में एक समाचार एजेंसी को भारतीय दूतावास के प्रवक्ता विनायक चव्हाण ने बताया कि बालाचंद्रन को ज्यादा चोट नहीं आई है। चव्हाण ने कहा, "उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन कोई गंभीर चोट नहीं आई है।" घटना इस प्रकार की है कि चीन स्थित एक कंपनी का मालिक कथित रूप से स्थानीय व्यापारियों के दो हफ्तों के बकाया का भुगतान किए बिना ही देश से बाहर भाग लिया जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों ने इस कंपनी से जुड़े दो भारतीय व्यापारियों को बंधक बना लिया और करीब 15 दिन से वे बंधक थे। यिउ कई जिंसों के व्यापार का एक बड़ा केंद्र है। यहां की अदालत में 46 साल के बालाचंद्रन करीब पांच घंटे से व्यापारियों की रिहाई की कोशिश में लगे थे। इसके बाद जब बालाचंद्रन के साथ दोनों भारतीय व्यापारी भी अदालत से बाहर जाने लगे तो स्थानीय व्यापारियों ने बालाचंद्रन की पिटाई शुरू कर दी। व्यापारियों से खचाखच भरी अदालत में काफी तमाशा खड़ा हो गया क्योंकि वे यह मांग कर रहे थे कि भारतीय व्यापारी पहले उनका लाखों युआन का बकाया चुकाएं।

गौरतलब है कि सीमा विवाद और भारतीय जमीन पर निर्वासित तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की मौजूदगी की वजह से भारत–चीन के रिश्तों में अक्सर खटास बनी रहती है। बढ़ते कारोबारी संबंधों के बावजूद तेजी से विकसित होते ये दोनों देश एक–दूसरे को संदेह की नजरों से देखते हैं क्योंकि इनमें अन्य देशों पर प्रभाव जमाए रखने एवं संसाधनों को लेकर प्रतिस्पर्धा है। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास की महावाणिज्यदूत रीवा गांगुली दास ने बीजिंग में कहा कि दीपक रहेजा एवं श्यामसुंदर अग्रवाल की रिहाई की कोशिश में लगे बालाचंद्रन की पिटाई की गई जिससे वे बेहोश हो गए। इस घटना पर चीनी अधिकारियों की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

चीन द्वारा अरुणाचल के अधिकारी को वीजा देने से इनकार, भारत ने अपने सैन्य प्रतिनिधिमंडल का दौरा रोका

(तिब्बतन रीव्यू डॉट नेट, 8 जनवरी)

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार भारत ने 30 सैन्य अधिकारियों के मजबूत प्रतिनिधिमंडल के 8 जनवरी को शुरू हो रहे चीन दौरे को रोक दिया है, क्योंकि चीन ने इस प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारतीय वायु सेना के एक कर्नल रैंक के अधिकारी को वीजा देने से इनकार कर दिया। चीन कई बार अरुणाचल राज्य के लोगों को वीजा देने से इनकार कर चुका है, यह दावा करते हुए कि अरुणाचल प्रदेश के लोग चीनी नागरिक हैं, इसलिए उन्हें अपने ही देश में यात्रा के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। खबर के अनुसार इसके बाद भारत ने पूरी यात्रा को ही रोक दिया। चीन ने ग्रुप कैप्टन एम पैंगिंग को वीजा देने से इनकार किया था जो सीमावर्ती राज्य असम के तेजपुर में सुखोई–30 एमकेआई लड़ाकू एयरबेस में चीफ ऑपरेशन अधिकारी के रूप में तैनात हैं। भारत और चीन के रिश्तों में यह नई खटास नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच हुए वार्षिक प्रतिरक्षा संवाद (एएडी) के एक महीने के भीतर ही पैदा हो गई है। इस वार्षिक बैठक में दोनों देशों ने यह तय किया था कि वे बड़े विश्वास बहाली उपाय के तहत 'सैन्य आदान–प्रदान बढ़ाएंगे'। दोनों देशों के पास दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं हैं और

1950 के दशक में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद इनमें 4,507 किलोमीटर लंबी अनसुलझी वास्तविक नियंत्रण रेखा है।

एएडी के बाद गत दिसंबर माह में 29 सदस्यीय चीनी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने चार दिन तक भारत का दौरा किया था जिसमें आगरा के पैराशूट रेजीमेंट का दौरा भी शामिल था। दूसरी तरफ, भारत के तीनों सेनाओं के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एक एयर वाइस मार्शल करने वाले थे और इस प्रतिनिधिमंडल को 10 से 13 जनवरी तक चीन के कई सैन्य केंद्रों का दौरा करना था तथा अपने चीनी समकक्षों से वार्ता करनी थी। इसके पहले जुलाई, 2010 में चीन ने थल सेना के तत्कालीन उत्तरी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. जसवाल को इस आधार पर वीजा देने से इनकार कर दिया था कि वह जम्मू–कश्मीर के 'विवादित एवं संवदेनशील' क्षेत्र में सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे भारत ने चीन के साथ सभी तरह के सैन्य आदान–प्रदान रोक दिए थे और पिछले साल जून में ही यह गतिरोध दूर हो सका, जब जम्मू–कश्मीर में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स की अगुवाई करने वाले मेजर जनरल गुरमीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल चीन गया।

वीजा विवाद के बाद आखिरकार भारतीय रक्षा प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा

(प्रेट्र, 9 जनवरी, 2012, बीजिंग)

एक छोटा भारतीय प्रतिनिधिमंडल आखिरकार यहां चार दिन के रक्षा आदान–प्रदान दौरे के तहत पहुंचा। पहले इस प्रतिनिधिमंडल की संख्या काफी बड़ी रहनी थी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के एक वायु सेना अधिकारी को वीजा न देने पर उठे विवाद के बाद दौरे का मूल कार्यक्रम टल गया था। 15 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एयर वाइस मार्शल पीएस मान कर रहे रहे हैं जो अपने चीनी समकक्षों से वार्ता करेंगे और चीन के रक्षा प्रतिस्थानों को भी देखने जाएंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में भारत की तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल कल (मंगलवार को) यहां चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) के जनरल स्टाफ मुख्यालय का दौरा करेगा और पीएलए के उप प्रमुख जनरल मा जियोशियन से मिलेगा। बीजिंग के अलावा प्रतिनिधिमंडल नानजिंग और शंघाई का भी दौरा करेगा। इसके अलावा इन अधिकारियों के नौसेना एवं वायु सेना बेस, एक थल सेना यूनिट और पीएलए के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा करने का कार्यक्रम है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले भारतीय वायु सेना के ग्रुप कैप्टन एम पैन्गिंग को यह कहते हुए वीजा देने से इनकार कर दिया था कि अरुणाचल तो दक्षिणी तिब्बत का ही हिस्सा है और वहां के नागरिक को चीन में आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। तब इस प्रतिनिधिमंडल का दौरा रोक दिया गया था और बाद में प्रतिनिधिमंडल की संख्या 30 से घटाकर 15 कर दी गई। यह कार्यक्रम दोनों देशों के बीच प्रतिरक्षा आदान–प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा है।

चीन का मौजूदा नेतृत्व तिब्बती समस्याओं को लेकर परेशान है।

शीर्ष जनरल ने चीन के बारे में चेताया

(टीओआई, 17 जनवरी, 2012)

भारत–चीन के बीच पिछले कुछ हफ्तों में बने गतिरोध की छाया द्विपक्षीय वार्ता पर पड़ रही थी, लेकिन इस बीच सीमा वार्ता के पंद्रहवें दौर की शुरुआत हो गई है, जिसमें यह प्रयास किया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच विश्वास की बहाली हो। हालांकि, इस प्रयास के जारी रहने के बावजूद भारतीय थल सेना के एक शीर्ष जनरल ने चेतावनी दी है। सभी महत्वपूर्ण उत्तरी कमान के प्रमुख जीओसी ने बताया है कि चीन की तरफ से अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देमछोक में हुआ अतिक्रमण भी शामिल है जो कि संभावित खतरे की घंटी है। लेफ्टिनेंट जनरल परनाइक को तो शायद खुले तौर पर यह कहने से रोक दिया गया हो कि भारत के लिए चीन एक खतरा है, लेकिन तिब्बत से होकर चीनियों के भारत पहुंचने की उनकी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिवशंकर मेनन संभवतः मंगलवार को अपने चीनी समकक्ष के साथ मिलकर सीमा प्रबंधन पर समझौते का विवरण तैयार करेंगे, लेकिन जनरल परनाइक के शब्द ऐसी किसी सहमति पर भारी पड़ते हैं।

वह बौद्धों के बीच अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद ही दलाई लामा के अगले पुनर्जन्म का चयन बिना किसी समस्या के कर सके।

बुद्ध की वापसी

(शोभन सक्सेना, टाइम्स ऑफ इंडिया)

क्या बौद्ध देश एक गुट बनाने के लिए करीब आ रहे हैं जो जितना धार्मिक हो उतना ही राजनीतिक भी हो? और क्या भारत इस गुट का नेता बनने को तैयार है? अगर ऐसा है तो चीन साफतौर से इससे खुश नहीं रहेगा। लेकिन एक हलचल तो शुरू हो ही

"यह वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यदि बौद्ध लोग खुद को एक नए शीतयुद्ध में पाते है जहां उन्हें दो प्रतिस्पर्धी खेमों में से एक का चयन करना पड़े। चीन आखिर एक ऐसे बैठक से खतरा क्यों महसूस कर रहा है जहां बौद्ध लोग बौद्ध धर्म की बातें कर रहे हैं?"

गई है। पहले वैश्विक बौद्ध समागम से संडे टाइम्स की रिपोर्ट।

उनके मुड़े हुए सिर से सुगंध आ रही थी, भूरे लबादे वाले थाई भिक्षु एक पंक्ति में आगे बढ़ रहे थे, उनकी आंखें जमीन की ओर थीं और हाथ प्रार्थना वाले ढोल पर हल्के–हल्के थाप दे रहे थे। उनके पीछे तिब्बती लामा, श्रीलंकाई भिक्षु और ताइवान के पुजारी थे–सभी काफी सुरुचिपूर्ण ढंग से चल रहे थे, मंत्र बुदुबदा रहे थे और एक जगह पर गोल घेरा बनाए हुए थे। इसके बाद पूरी भीड़ में एक सिहरन सी हो गई क्योंकि नेहरू पार्क में दलाई लामा पहुंच चुके थे और उन्होंने एक नए खुदे गड्ढे में बोधि वृक्ष की शाखा का रोपण किया (यह शाखा उसी पीपल के पेड़ की है जिसके नीचे 2600 साल पहले बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और जिसे छठी शताब्दी में बौद्ध विरोधी मूर्तिभंजक बंगाल नरेश शशांक ने काट और जला दिया था। गत 30 नवंबर को दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध समागम में एक नए वैश्विक बौद्ध मंच बनाने का निर्णय लिया गया जिसका मुख्यालय भारत में होगा। इस समागम में 46 देशों (थेरवाड, महायान एवं वज्रयान परंपरा से जुड़े) के प्रतिनिधियों को बोधि वृक्ष की शाखा दी गई जिसे वे अपने देश में लगाएंगे। कई देशों के नेताओं ने यह पौधा दलाई लामा से हासिल किया जिन्होंने समागम में समापन भाषण दिया। इस समागम के संदेश को कोई भी समझ सकता हैः बौद्ध धर्म दुनिया भर में ज्यादा संगठित होने को तैयार है, भारत इस एकता का नया केंद्र होगा और दलाई लामा को सभी बौद्धों का गैर आधिकारिक नेता मान लिया गया है। दिल्ली समागम का आयोजन करने वाले अशोक अभियान के प्रमुख लामा लोबसांग ने कहा, "सभी बौद्ध देश यह महसूस करते हैं कि बुद्ध की भूमि भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अब सभी बौद्ध संगठन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के तहत होंगे जिसका केंद्र भारत में होगा।" इस विचार को स्वीकर्षति मिली है। श्रीलंका के महाबोधि सोसाइटी के प्रमुख बनागला उपततिसा ने कहा, "यदि भारत में कोई पहले करे तो यह देश बौद्ध दुनिया का नेता बन सकता है।" लेकिन निश्चित रूप से कोई है जिसे यह स्वीकार नहीं होगा। बौद्ध समागम की शुरुआत से एक दिन पहले 26 नवंबर को चीन ने भारत के साथ सीमा वार्ता को स्थगित कर एक राजनयिक तूफान खड़ा कर दिया क्योंकि भारत ने इसी समय नई दिल्ली में हो रहे बौद्ध समागम को रोकने की उसकी मांग को अनसुना कर दिया था। इसके पहले इस समागम में आमंत्रित 35 चीनी भिक्षुओं को आने नहीं दिया गया था, तब ही यह साफ हो गया था कि इस समागम से चीन खुश नहीं है। समागम में शामिल होने आए आस्ट्रेलिया के शिक्षाविद और पर्यावरण आंदोलनकारी गैब्रिएल लेफिते ने कहा, "इस सम्मेलन ने बिखरे हुए बौद्ध समुदाय को बहुत साफ तौर पर इस बात की याद दिलाई है कि भारत बौद्ध धर्म का घर है। चीन यह सुनिश्चित करने को लेकर काफी सक्रिय रहा है कि बौद्ध पृष्ठभूमि का कोई भी व्यक्ति चीन के साथ जुड़ाव महसूस करे, लेकिन बौद्ध परिवार की पुनर्बहाली को लेकर भारत की गति थोड़ी धीमी है।"

आधिकारिक रूप से नास्तिक चीन का यह बौद्ध प्रेम कोई अचानक नहीं जग पड़ा है। चीन एक वैश्विक बौद्ध नेता के रूप में दलाई लामा की बढ़ती महत्ता से चिंतित है। वह बौद्धों के बीच अपनी विश्वसनीयता भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद ही दलाई लामा के अगले पुनर्जन्म का चयन बिना किसी समस्या के कर सके। पेइचिंग विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र में पढ़ाने वाले बिनोद सिंह बताया, "चीन का मौजूदा नेतृत्व तिब्बती समस्याओं को लेकर परेशान है। मुख्यभूमि चीन में तिब्बती बौद्ध भिक्षओं के आत्मदाह की कई घटनाएं सामने आई हैं। दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर जल्द निर्णय की जरूरत महसूस की जा रही है।" चीन के सामने एक और समस्या भी है। वह अपनी आर्थिक बढ़त दर से भले ही दुनिया को चकित कर रहा हो, लेकिन अपने घर में सामाजिक अशांति और धर्म के बढ़ते असर को रोक पाने में नाकाम दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन में बौद्धों की संख्या 10 करोड़ के आसपास पहुंच गई है जिनमें से बहुत लोग तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चीन में हाल तक तैनात रहे एक भारतीय राजनयिक ने कहा, "देर से ही सही चीनी नेतष्त्व अब समरस समाज की बात करने लगा है और उन्होंने सभी धर्मों पर लगे प्रतिबंध कुछ कम किए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अब लामाओं के पुनर्जन्म प्रक्रिया में हिस्सा लेने लगी है। वे अपनी जनता पर नियंत्रण रखने के लिए बौद्ध धर्म पर नियंत्रण करना चाहते हैं। बौद्ध देशों के नेतष्त्व और पूर्वी एशिया में व्यापारिक हितों को लेकर चीन का भारत से टकराव है जिनको चीन अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है।"

इसलिए यह लड़ाई सिर्फ एशिया की आत्मा को लेकर नहीं है। बौद्ध धर्म पर चीन एवं भारत के बीच टकराव इस क्षेत्र में एक नए शीतयुद्ध की शुरुआत कर सकता

है जहां धर्म और व्यावसायिक हित की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेइचिंग विश्वविद्यालय के विनोद सिंह ने कहा, "बहुत से चीनियों का यह मानना है कि चीन विश्व समुदाय में अपने दोस्तों को खो रहा है और भारत दूसरी तरफ वियतनाम, म्यांमार एवं मंगोलिया जैसे कई नए दोस्त बना रहा है। चीन में तो यह भी कहा जा रहा है कि फिलहाल भारत, जापान और अमेरिका मिलकर चीन को घेरने की रणनीत पर काम कर रहे हैं।" क्या इसका मतलब यह है कि शीतयुद्ध की अब खुले तौर पर शुरुआत हो चुकी है?

गैब्रिएल लेफिते ने कहा, "यह वास्तव में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा, यदि बौद्ध लोग खुद को एक नए शीतयुद्ध में पाते है जहां उन्हें दो प्रतिस्पर्धी खेमों में से एक का चयन करना पड़े। चीन आखिर एक ऐसे बैठक से खतरा क्यों महसूस कर रहा है जहां बौद्ध लोग बौद्ध धर्म की बातें कर रहे हैं?"

लेकिन बौद्ध भिक्षुओं से डरने की चीन के पास कई वजहें हैं। हाल के वर्षों में बौद्ध भिक्षुओं ने एशिया की सड़कों पर राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया है। म्यांमार में साल 2007 में जुंटा के खिलाफ एक जन विद्रोह का नेतष्त्व भिक्षुओं ने किया था और अब वह धीरे–धीरे लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहा है। थाइलैंड में एक बौद्ध गुट ने साल 2006 में थाकसिन शिनवात्रा को सत्ता से हटाने में मदद की थी। इसी प्रकार ताइवान में बौद्धों ने ताकतवर राजनीतिक आंदोलन चलाए हैं। ऐसे इलाके में बौद्ध भिक्षु खुले तौर पर राजनीतिक हो रहे हैं और राष्ट्रवाद के मुख्य प्रेरक बन रहे हैं जिसे चीन अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है, इसलिए वह इसके तिब्बत पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंतित है। इन सभी देशों में दलाई लामा का सम्मान और स्वागत किया जाता रहा है, इसलिए अचरज की बात नहीं है कि चीन ने दिल्ली के समागम में तिब्बती आध्यात्मिक नेता के भाषण को रद्द करने के लिए दबाव बनाया। अशोक मिशन के लामा लोबसांग कहते हैं, "दलाई लामा तो समूचे मानवता के हैं। चीन ने न केवल दलाई लामा की उपस्थिति पर आपत्ति जताई है, बल्कि वह चाहता था कि पूरा सम्मेलन की ही रद्द कर दिया जाए। मैं नहीं समझ पा रहा कि चीन आखिर किस बात से डरा हुआ है।"

असल में चीन डरा हुआ नहीं है, बल्कि वह सचेत है क्योंकि वह खुद बौद्ध देशों के अगुआ बनने का सपना देख रहा है। चीन सतर्कता से खुद को एक बौद्ध ताकत के रूप में स्थापित करने में लगा हुआ है। साल 2006 में उसने पहले विश्व बौद्ध मंच का आयोजन झेज्यान में किया था। इस तरह के दूसरे मंच का आयोजन साल 2009 में वुक्सी में हुआ। भारतीय राजनयिक ने बताया, "इन दोनों आयोजनों में चीन ने गेनकेन नोर्बू को पेश किया जिन्हें शीर्ष बौद्ध नेता दलाई लामा से पंचेन लामा के रूप में मान्यता नहीं मिली है।" उनका खेल स्पष्ट है, "दलाई लामा के बिना बौद्ध दुनिया को संगठित करना।" इस खेल का विस्तार अब लुंबिनी तक कर दिया गया है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था। चीन ने अरबों डॉलर की एक परियोजना का प्रस्ताव रखा है जिससे लुंबिनी को बौद्धों के मक्का में बदला जा सके। चीन अपने तिब्बत रेलमार्ग का विस्तार भी लुंबिनी तक करना चाहता है। अस्सी के दशक से ही दलाई लामा को लुंबिनी जाने की इजाजत नहीं दी गई है। तो भारत एवं चीन के बीच बौद्ध धर्म को लेकर अगला शीतयुद्ध नेपाल में हो सकता है।

तिब्बती इस्टेब्लिशमेंट 22 का गठन नवंबर 1962 में किया गया।

1971 के युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले तिब्बती

क्लॉड आर्पी

दापोन रटुक नवांग

दापोन रटुक नावांग तिब्बत की स्वैच्छिक स्वतंत्रता सेनानी बल के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। यह तिब्बत का एक गुरिल्ला संगठन है जो चीनी शासन के खिलाफ लड़ता रहा है और जिसकी मार्च 1959 में दलाई लामा को सुरक्षित भारत पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साल 1962 में हुए चीन–भारत सीमा युद्ध के बाद रटुक नावांग ने एक गुप्त तिब्बती रेजीमेंट का नेतृत्व किया जिसे 'विशेष सीमा बल (एसएफएफ)' या 'इस्टेब्लिशमेंट 22' कहा जाता था। इस बल का बेस तत्कालीन उत्तर प्रदेश में देहरादून के नजदीक था। अब 84 साल के हो चुके रटुक नावांग दिल्ली की मजनू का टीला स्थित तिब्बती बस्ती में रहते हैं। हाल में उन्होंने तिब्बती भाषा में अपने संस्मरण प्रकाशित किए हैं जिसमें उन्होंने पूर्वी तिब्बत के खम प्रांत में अपनी शुरुआती जीवन और फिर भागकर भारत आने एवं 1971 के युद्ध में तिब्बती तैयारी का हिस्सा बनने के बारे में बताया है। एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में एसएफएफ की भूमिका के बारे में क्लॉड आर्पी को बताया। सल 1971 में रटुक नावांग इस बल के 'दापोन' थे जिसका मतलब

विशेष सीमा बल या इस्टेब्लिशमेंट 22 नाम का यह तिब्बती रेजिमेंट आधिकारिक रूप से कभी भी भारतीय सेना का हिस्सा नहीं रहा है।

सच तो यह है कि असल युद्ध हम लड़े थे और हमारे कई लोग मारे भी गए लेकिन बाद में पूरा श्रेय मुक्ति वाहिनी को मिल गया (क्योंकि तिब्बती सेना मुक्ति वाहिनी के भेष में ही लड़ रही थी)

होता है ब्रिगेडियर। उन्हें राजनीतिक नेता भी माना जाता था। साल 1971 के भारत–पाक युद्ध का एक पहलू यह भी है कि इस बात को कभी प्रचारित नहीं किया गया कि इसमें तिब्बती सेनाएं भी शामिल हुई थीं। इस युद्ध के आधिकारिक इतिहास में सभी विजयी संघर्षो की चर्चा हुई है, लेकिन इनमें तिब्बती रेजीमेंट का कोई उल्लेख नहीं है। इस बात का आज कोई दस्तावेज भी नहीं है जो यह साबित कर सके कि इस युद्ध में तिब्बती सैनिक शामिल हुए थे।

हम बांग्लादेश अभियान में तिब्बती सैनिकों की भूमिका के बारे में आपसे और जानने को इच्छुक हैं। हमें यह जिज्ञासा भी है कि क्या इस बारे में तिब्बती सैनिकों को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (दलाई लामा की निर्वासित सरकार) से कोई निर्देश मिले थे?

मैंने इन सभी मसलों को अपने संस्मरण में शामिल किया है (धर्मशाला के आमनी माछेन इंस्टीट्यूट द्वारा तिब्बती भाषा में प्रकाशित)। विशेष सीमा बल या इस्टेब्लिशमेंट 22 नाम का यह तिब्बती रेजिमेंट आधिकारिक रूप से कभी भी भारतीय सेना का हिस्सा नहीं रहा है। असल में इसकी स्थापना साल 1962 के भारत–चीन युद्ध के दौरान हुई थी। इस रेजीमेंट का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना की सहायता से चीनी सेना से लड़ाई करना था। जब यह बल बना तो हम यह सोचते थे कि इस सैन्य अभियान का केंद्र भारतीय सीमा के पास तिब्बत में ल्हुंत्से जोंग को बनाएंगे। योजना यह थी कि इस बल के गठन से 5 से 6 महीने के भीतर ही चीनी सेना से सैन्य लड़ाई शुरू की जाए। लेकिन भारत–चीन के बीच युद्ध अचानक ही बंद हो गया (22 नवंबर को) और शांति बनाए रखने के भारी अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से चीन के साथ फिर कोई सैन्य संघर्ष नहीं हुआ। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट 22 रेजिमेंट की सेवाओं का इस्तेमाल योजना के मुताबिक नहीं हो पाया।

इस्टेब्लिशमेंट 22 के बारे में कुछ और बताएं।

चीन ने साल 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया। इसके बाद साल 1960 में भारत सरकार ने 'भारत–तिब्बत सीमा बल' का गठन किया। तिब्बती इस्टेब्लिशमेंट 22 का गठन नवंबर 1962 में किया गया।

एसएफएफ को युद्ध में भागिल होने का आदेश कहां से मिला?

भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी मेजर जनरल सुजान सिंह उबान से जो उस समय तिब्बत सीमा बल के कमांडर थे। (एसएफएफ को इस्टेब्लिशमेंट 22 या सिर्फ 22 नाम मिला क्योंकि जनरल उबान पहले 22 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर रह चुके थे।)

नई दिल्ली में सेना की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी, बाद में हमने यह सुना कि बांग्लादेश युद्ध के दौरान जनरल उबान ने खुद ही इस्टेब्लिशमेंट 22 का नेतृत्व करने की इच्छा जताई। एस.एस. उबान और मेरे एक सहयोगी दापोन जाम्पा कालदेन स्वेच्छा से बांग्लादेश युद्ध में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी योजनाओं के बारे में बताया। पहले तो मैंने उनका साथ देने से इनकार कर दिया क्योंकि स्वेच्छा से युद्ध में शामिल होना मुझे 'गैर कानूनी' लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि भारत सरकार या केंद्रीय तिब्बती प्रशासन से आदेश मिलने के बाद ही मैं इस अभियान में शामिल हो सकता हूं। इसके अलावा मैंने उनसे यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट 22 का गठन 'भारत के लिए' लड़ने के लिए नहीं बल्कि चीनियों से लड़ने के लिए हुआ है। वास्तव में यही वजह थी जिससे हमें भारतीय सैनिकों के मुताबिक कम वेतन मिलता था। हम भारतीय सेना के नियमित हिस्सा नहीं थे। जब इस रेजीमेंट का गठन हुआ था तो इस बात पर परस्पर सहमति बनी थी कि हम चीनियों से लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी मैंने जनरल उबान और दापोन जाम्पा कालडेन से कहा कि यदि हमें भारत सरकार से औपचारिक आदेश मिलता है तो हम इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं।

क्या दलाई लामा के बड़े भाई ग्यालो थोनडुप ने तिब्बती सैनिकों को बांग्लादेश युद्ध में भागिल होने का निर्देश दिया था या किसी और ने?

धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सुरक्षा विभाग ने हमें ऐसा निर्देश दिया था। विभाग ने हमें एक बैठक में बुलाया था। उन्होंने हमसे कहा कि अब इसके सिवा कोई विकल्प नहीं बचा है कि 'भारत के लिए' हम लड़ाई लड़ें। उन्होंने हमसे कहा कि भारत सरकार बहुत संकट की स्थिति में है और हम अगर लड़ाई में शामिल हुए तो बहुत से भारतीयों की जानें बचा सकते हैं।

क्या आपका आर.एन. काव से कोई संपर्क था जिन पर तब कैबिनेट सचिवालय में बाह्य इंटेलीजेंस की जिम्मेदारी थी?

जी हां, आर.एन. काव भारत सरकार के एक उच्च स्तरीय अधिकारी थे और वह इंदिरा गांधी के करीबी

सहयोगी थे। लेकिन हमारे कमांडर जनरल एस.एस उबान ही थे। उन्होंने नई दिल्ली की यात्रा की थी और बांग्लादेश युद्ध में एसएफएफ का नेतृत्व करने की अपनी योजना के बारे में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को भी बताया था। जब वह हमारे बेस में (उत्तर प्रदेश) वापस लौटे तो उन्होंने जाम्पा कालदेन और मुझे केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के अधिकारियों से मिलने के लिए धर्मशाला भेजा। हमने पहले केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) को इस युद्ध में शामिल होने की इच्छा न होने के बारे में बताया, लेकिन सीटीए इस युद्ध में इस्टेब्लिशमेंट 22 को भेजने का निर्णय ले चुका था इसलिए हमें इसमें शामिल होना पड़ा।

क्या इस निर्णय में आर.एन. काव भी भाामिल थे? ?

आर.एन. काव एक उच्च स्तरीय अधिकारी थे और सेना के आदमी नहीं थे। इसलिए इस तरह के अभियान में उनकी सीधी संलिप्तता नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमें खुद को तैयार रखने और अच्छी तरह से लड़ाई करने के बारे में निर्देश एवं सलाह दिए।

क्या श्री काव ने जनरल उबान को आदेश दिया था?

आर.एन. काव एक उच्च स्तरीय अधिकारी थे, इसलिए उनके पास ज्यादा अधिकार थे। जब हमने चटगांव पर कब्जा किया तो काव ने इस्टेब्लिशमेंट 22 रेजीमेंट का दौरा किया और कई सैनिकों को अवॉर्ड दिए तथा अपने भाषण में तिब्बती रेजीमेंट की ऐतिहासिक जीत की तारीफ की। आर.एन. काव काफी देशभक्त व्यक्ति थे।जब युद्ध में शामिल होने का निर्णय हुआ तो दापोन धोनडुप ग्यातोत्सांग (जिनका 1971 के युद्ध में निधन हो गया), दापोन पेकर थिनले और खुद मैंने रेजीमेंट को तीन यूनिट में बांट लिया। हमने तय किया कि इस युद्ध में हम तीनों लोग एक–एक टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे। अपनी उम्र के नाते सैन्य अनुभव होने के बावजूद दापोन जाम्पा कालदेन इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि, उन्होंने भारत सरकार और इस्टेब्लिशमेंट 22 के बीच प्रशासनिक सेतु की भूमिका निभाई। ग्यालो थोनडुप देहरादून में गठित होने वाले एसएफएफ के मुख्य रणनीतिकार थे, लेकिन तिब्बती सैनिकों को बांग्लादेश युद्ध के लिए भेजने के निर्णय में वह शामिल नहीं थे। जब तिब्बती शरणार्थी पहली बार भारत आए थे तो भारत सरकार ने उनसे साफ तौर पर आग्रह किया था कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल न हों। बांग्लादेश युद्ध से काफी पहले ही ग्यालो थोनडुप और एंड्रग गोनपो टाशी (तिब्बत में तिब्बत स्वयंसेवी बल के संस्थापक) अपने सैन्य पदों से इस्तीफा दे चुके थे।

जनरल उबान ने उत्तर प्रदेश में मुक्ति वाहिनी के कितने जवानों को प्रशिक्षण दिया था?

पाकिस्तान में जब शेख मुजिबुर रहमान को जेल में डाल दिया गया तो उनके एक हजार से ज्यादा समर्थक जान बचाते हुए भारत आ गए। इनमें से कई को एसएफएफ शिविर के पास ठहराया गया। हमने उन्हें सैन्य संघर्ष का प्रशिक्षण दिया जिसके बाद उन्हें 'मुक्ति वाहिनी' नाम दिया गया। उनमें से कई लोग मुजिबुर रहमान के रिश्तेदार भी थे। बाद में युद्ध के दौरान वे हमारे मार्गदर्शक और संपर्क सूत्र बने लेकिन वे हमारे साथ लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। सच तो यह है कि असल युद्ध हम लड़े थे और हमारे कई लोग मारे भी गए लेकिन बाद में पूरा श्रेय मुक्ति वाहिनी को मिल गया (क्योंकि तिब्बती सेना मुक्ति वाहिनी के भेष में ही लड़ रही थी)

क्या मुक्ति वाहिनी भी जनरल उबान के कमान के तहत ही थी?

जी हां, जनरल उबान ने ही मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण दिया था।

आप और आपके दो साथी दापोन बांग्लादेश कब पहुंचे?

हम नवंबर 1971 में बांग्लादेश पहुंचे थे, तब मैं 39 साल का था।

आप बांग्लादेश युद्ध की भुरुआत से पहले गए थे या युद्ध के दौरान?

हम बांग्लादेश युद्ध की शुरुआत से पहले ही गए थे। हम बांग्लादेश युद्ध के दौरान चीनियों से गुरिल्ला युद्ध लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे मुख्य शत्रु मिजो आतंकवादी थे। तिब्बतियों को भारतीय सेना ने प्रशिक्षण दिया था तो मिजो अलगाववादियों को पाकिस्तान ने प्रशिक्षण दिया था।

आप कब और कैसे गए?

हम उत्तर प्रदेश में स्थित इस्टेब्लिशमेंट 22 बेस से हवाई जहाज से दमदम एयरपोर्ट (कलकत्ता) गए। दमदम से हम मिजोरम के देमागिरी में मोटर से पहुंचे। इसमें करीब तीन दिन लग गए। बांग्लादेश सीमा (चिटागॅग पहाड़ियों का रास्ता) पर पहुंचने के बाद हमारी एक बैठक हुई जिसके बाद हमें सीधे युद्ध में भेज दिया गया। हम युद्ध के लिए 12 नवंबर को गए थे और 28 दिनों तक लड़ाई लड़ते रहे जिसमें

हमसे अनुरोध किया गया कि इस कौशल का इस्तेमाल हम बांग्लादेश के युद्ध में भी करें।भारतीय अधिकारियों ने हमें यह भरोसा दिया था कि भारतीय सेना तिब्बत के आंदोलन में तिब्बतियों का साथ देगी।उनका तर्क यह था कि तिब्बती सैनिक अकेले चीनी सेना को नहीं हरा सकते।

आखिरकार विजय मिली। पाकिस्तान की तरफ के बहुत से सैनिक मारे गए और बहुतों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

इस युद्ध में जनरल उबान का सैन्य लक्ष्य क्या था?

हमें चीनियों से कमांडो लड़ाई लड़ने का गहन प्रशिक्षण मिला था। हमसे अनुरोध किया गया कि इस कौशल का इस्तेमाल हम बांग्लादेश के युद्ध में भी करें। भारतीय अधिकारियों ने हमें यह भरोसा दिया था कि भारतीय सेना तिब्बत के आंदोलन में तिब्बतियों का साथ देगी। उनका तर्क यह था कि तिब्बती सैनिक अकेले चीनी सेना को नहीं हरा सकते। इस वजह से हमने बांग्लादेश युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। हमें उम्मीद थी कि एक दिन भारतीय सेना चीनियों से लड़ने में हमारी सैन्य मदद करेगी।

युद्ध पर जाने से पहले क्या जनरल उबान ने आपको ऐसा कोई निर्देश दिया था कि पाकिस्तान के किस खास जगह या सैन्य अड्डे पर कब्जा करना है?

हमारे पास उस इलाके (चिटागॅग पहाड़ियों) का एक नक्शा था। हमारी प्रत्येक यूनिट (बटालियन) में एक हजार से थोड़े ज्यादा ही सैनिक थे जिनमें तिब्बती सैनिक और कुछ मुक्ति वाहिनी के साथी थे। जनरल उबान तिब्बती विशेष सीमा बल के कमांडर थे। वे हमें हिंदी में निर्देश देते थे (इसका तिब्बती में अनुवाद करने वाले लोग थे) । वे हमें बताते थे कि कहां जाना है और बाद में वाकी–टाकी के द्वारा हम उन्हें यह बताते रहते थे कि हम कहां पहुंचे हैं और तब हमें वे यह बताते थे कि आगे क्या करना है। तीन तिब्बती बटालियन में तीन तिब्बती दापोन और तीन भारतीय कर्नल थे। तीनों दापोन और तीनों कर्नल हमेशा रणनीतियों पर चर्चा करते रहते थे, लेकिन इसकी जानकारी जनरल उबान को दी जाती थी और वही निर्णय लेते थे।

देमागिरी के अलावा तिब्बती सैनिक अन्य तिब्बती सैनिक अन्य किन जगहों पर लड़े थे?

देमागिरी मुख्य सैन्य अड्डा था। इस अड्डे की सुरक्षा के लिए करीब 100 तिब्बती सैनिक और 100 मुक्ति वाहिनी के जवान तैनात थे। देमागिरी में कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी तैनात थे, इसके अलावा यहां एक अस्पताल भी था जिसमें युद्ध में घायल सैनिकों का उपचार किया जाता था। ज्यादातर डॉक्टर भारतीय सशस्त्र मेडिकल कॉर्प्स के मेजर और कैप्टन थे। युद्ध से काफी पहले यह सब तैयारी कर ली गई थी। गंभीर रूप से घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर से दूसरे अस्पतालों में ले जाया जाता था, लेकिन युद्ध चिटागॅग की पहाड़ियों के जंगल में हो रहा था, इसलिए वहां हेलीकॉप्टर उतारना कठिन था। इसलिए कई घायलों को नदियों के रास्ते नावों से भेजा जाता था।

वास्तविक लड़ाई शुरू होने के बाद भारतीय सेना देमागिरी कब पहुंची, क्या भारतीय सैनिक तिब्बती सैनिकों की सहायता करने में सक्षम थे?

जी नहीं, भारतीय सैनिक हमारी मदद करने लायक नहीं थे। इसी प्रकार तिब्बती सैनिक भी भारतीय सैनिकों की मदद नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों का प्रशिक्षण अलग तरह के सैन्य युद्ध के लिए हुआ था। तिब्बती कमांडो को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण मिला था, जबकि भारतीय सैनिकों को नगरीय लड़ाई का।

क्या आपके सैन्य लक्ष्यों की पूर्ति हो पाई?

दस दिन के भीतर ही हमने दुश्मनों के सिर्फ दो अड्डों को छोड़कर बाकी सब पर कब्जा कर लिया। ज्यादातर दुश्मन सैन्य अड्डों पर 50 या इसके आसपास सैनिक ही थे और जब हमने उन पर हमला किया तो वे बड़ी संख्या में सैनिकों से घिर गए और कुछ ही घंटों की लड़ाई में उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा।इसके बाद 16 दिसंबर को जब यह खबर आई कि भारतीय सेना ने ढाका पर चढ़ाई कर दी है तो ज्यादातर बची हुई छोटी सैन्य टुकड़ियों ने आत्मसमर्पण कर दिया।

बांग्लादेश युद्ध में विजय के बाद क्या आपआधिकारिक विजय परेड में भाामिल होने के लिए चिटागॅग गए?

जनरल उबान ने चिटागॅग के आधिकारिक विजय समारोह में हमारे जाने की व्यवस्था की थी। लेकिन हम जा नहीं पाए क्योंकि तिब्बती सैनिक कई जगहों में बिखरे हुए थे। इसलिए जनरल उबान और आर.एन. काव चिटागॅग के आधिकारिक समारोह में शामिल होने गए और उन्होंने युद्ध में योगदान करने वाले तिब्बती सैनिकों को अनुलाभ देने और पुरस्कृत करने के बारे में बात की। हम वापस लौट आए और हमने अपने अड्डों में विजय समारोह मनाया।

क्लाड आर्पी का नोटः बताया जाता है कि जनरल उबान की योजना तिब्बती सैनिकों का इस्तेमाल चिटागॅग पर कब्जे में करने की थी, लेकिन एसएफएफ के पास इस तरह का अभियान चलाने के लिए न तो तोपखाना था और न ही हवाई सहयोग। लेकिन वे चिटागॅग की पहाड़ियों में कई छोटे अभियानों में शामिल हुए जिनमें कलूरघाट रेडियो स्टेशन पर कार्रवाई, रंगमती जिले में चिटागॅग से करीब 65 किलोमीटर ऊपरी धारा पर कर्नाफुली नदी पर बने कई पुलों और कपताई बांध पर हमला शामिल था। उन्होंने पाकिस्तानी 97 आज़ाद ब्रिगेड और दूसरे कमांडो बटालियन की पिछली प्रतिरक्षा पंक्ति काटकर उन्हें बर्मा जाने से रोका। 1971 की लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट 22 के 56 जवान शहीद हो गए और 190 जवान घायल हुए। वीरतापूर्ण कार्य के लिए भारत सरकार ने 580 सैनिकों को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन किसी तिब्बती सैनिक को कोई बहादुरी अवॉर्ड नहीं दिया गया। तिब्बती सैनिक केवल 'चिटागॅग के फैंटम' थे जो एक ऐसा युद्ध लड़ रहे थे जो उनका अपना नहीं था बल्कि मुक्ति वाहिनी के वेश में था।

इस साक्षात्कार के दौरान अनुवाद के लिए मैं जामफेल शुनु और तेनजिन लेक्शे का ऋणी हूं।